राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

संपादक - विवेक जैन

टाइटल कोड - MPHIN37675

Email- haldharkisankgn@gmail.com

वर्ष 01 अंक 11 | जनवरी 2023 | पृष्ठ-8 मूल्य -5.00 रुपये

अब विदेशों में तड़का लगाएगी निमाड़ की मिर्च यूरोप के लिए रवाना हुआ पहला लॉट

डालकी के 100 किसानों ने एफपीओ में पाई सफलता

हलधर किसान (विवेक जैन) 9826525025। भारत के विकास में किसानों का महत्वपूर्ण स्थान है। कोरोना संकट में भी किसानों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। किसानों की मेहनत का नतीजा है कि आज दूसरे देशों में अनाज, फसल और सब्जियां निर्यात की जा रही है। खेती.किसानी के क्षेत्र में उभरने वाली इस सफलता का श्रेय किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को भी जाता है। एक जिला एक उत्पाद में चिन्हित मिर्च की फसल को विदेश में निर्यात करने में सफलता प्राप्त हो गई है। खरगोन जिले के डालकी के किसान उत्पादक समूह टेराग्लेब को यह सफलता मिली है। इसके लिए किसानों ने शुरुआत से ही मिर्च को प्रमुखता देते हुए विदेशों में निर्यात करने का सपना संजोया था। आज वो ही दिन है जब पहली बार किसानों द्वारा उत्पादित मिर्च किसान ही विदेश निर्यात कर रहे हैं। मुम्बई पोर्ट से यूरोपीय देशों में निर्यात हुई है। टेराग्लेब एफपीओ के किसान और फाउंडर बालकृष्ण पाटीदार ने बताया कि आज से तीन वर्ष पूर्व बने इस समूह ने शुरुआत से ही यही कल्पना की थी कि उनकी मिर्च विदेशों में निर्यात हो इस लिहाज से यह उनकी कामयाबी का बहुत बड़ा दिन है। मुम्बई पोर्ट से आज डालकी के 8 किसानों की कुल 55 क्विंटल (5.50) टन मिर्च का निर्यात हो गया है।

प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग किये बिना लिया उत्पादन

समूह ने पहले स्टडी कर पता लगाया कि क्यों खरगोन की मिर्च लोकप्रिय होने के बावजूद विदेशों में निर्यात नहीं हो रही है? इसका एक कारण विदेशों में प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग है। इन रसायनों का खरगोन के किसान बड़ी मात्रा में करते है। ऐसे रसायनों को अलग कर आईपीएम टेक्नोलॉजी के अनुसार 62 किसानों के साथ 500 एकड़ में मिर्च की खेती प्रारम्भ की। सबसे पहले मिट्टी परीक्षण कर पता लगाया कि मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है। इसके बाद एक जैसी तकनीक अपनाकर उत्पादन प्रारम्भ किया। 62 किसानों के 10 सेम्पल्स केरला की एविटी लेब में टेस्ट भेजे गए जिसमें 8 सेमपल्स पास हो गए। मतलब मिर्च में प्रतिबंधित रसायन जैसे- प्रोपिनोफॉस, ट्रेजोफॉस, क्लोरोपारीफॉस, और मोनोक्रोटफॉस के अलावा भी कई रसायनों से मुक्त पाया गया। ये रसायन अमेरिका सहित यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित है और हमारे जिले की मिर्च में इनकी अत्यधिक मात्रा होने से निर्यात नहीं हो पा रही थी। इसी बात का फायदा अन्य व्यापारी उठाते थे और मिक्स कर दो राज्यों की मिर्च का सीधा निर्यात कर देते थे।

किसानों को तकनीक से बाजार तक कि सुविधा दे रहा है समूह

टेराग्लेब समूह किसानों को मिट्टी परीक्षण से लेकर बीजों के अलावा संबंधित वॅसल में उपयोग होने वाली तकनीक तथा अच्छे दाम दिलाने के लिए बाजार और व्यापारी तक उपलब्ध कराने की सुविधा दे रहा है। इसमें किसानों को कृषि उपकरण भी किराए पर उपलब्ध करा रहा है। साथ ही कीटनाशक छिड़काव के लिए समूह ने किसानों को ड्रोन भी उपलब्ध कराए है। समूह के माध्यम से कुछ किसान अरहर प्याज और मूंग जैसी फसलों के बीज भी तैयार कर रहे हैं।

ऐसे तैयार हुआ एफपीओ

आज से 5 वर्ष पूर्व उद्यानिकी और कृषि विभाग ने किसानों के एफपीओ बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी पीएस बड़ोले ने बताया कि किसानों के एफपीओ बनाने के लिए कई वर्षों से कार्य हो रहे हैं। गुंटूर सहित अन्य स्थानों पर विजिट और प्रशिक्षण भी आयोजित किये गए। शासन की पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए यह एफपीओ तैयार होकर अब विदेश तक अपनी फसल निर्यात कर रहा है। यह उनकी और हमारे प्रयासों के लिए अच्छे संकेत है।

गेहूं-चावल बिगाड़ रहे रसोई का बजट

हलधर किसान। 98262 25025
मोटे अनाज की खुदरा महंगाई दर घटने का नाम नहीं ले रही है, भले ही कुल मिलाकर खाद्य महंगाई दर में नरमी आई है। खराब मौसम की मार से इन अनाज का उत्पादन घटा है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। नवंबर में मोटे अनाज की महंगाई दर अक्टूबर महीने के 12.08 फीसदी से बढ़कर नवंबर में 12.96 फीसदी हो गई। ऐसा तब हुआ है, जब समग्र महंगाई दर 11 महीनों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 6 फीसदी के लक्ष्य के भीतर आ गई। खाद्य महंगाई दर भी 11 महीने के सबसे निचले स्तर 4.67 फीसदी पर आ गई है।

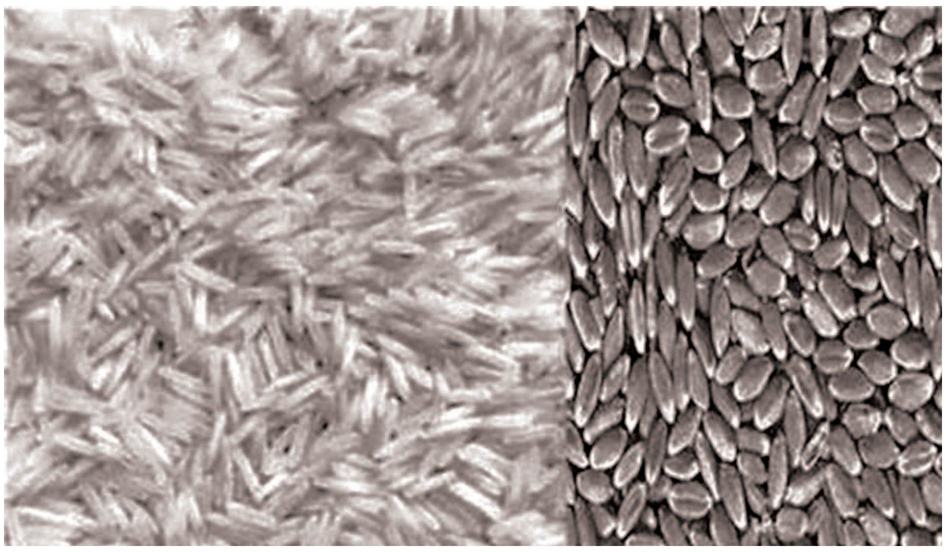

रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी इन प्रमुख जिंसों के रास न आई

यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की भारी कमी के कारण भी कीमतें बढ़ीं। इसी तरह, चावल के मामले में भी खराब मौसम ने खेल दिखाया और पूर्वी भारत में सूखे ने चावल के उत्पादन को नीचे खींच लिया। पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक, हाल में समाप्त हुए खरीफसीजन में चावल का उत्पादन 10.49 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 6.05 फीसदी कम होगा।

गेहूं की खुदरा महंगाई दर अक्टूबर के 17.64 फीसदी से बढ़कर नवंबर में 19.67 फीसदी हो गई। साल की शुरुआत में यह महज 5.1 फीसदी थी और चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में बढ़कर 9.59 फीसदी हो गई। उस स्तर की तुलना में यह नवंबर में दोगुने से अधिक हो गई है। एक अन्य प्रमुख अनाज चावल की महंगाई दर अक्टूबर के 10.21 फीसदी से बढ़कर नवंबर में 10.51 फीसदी हो गई। जनवरी में यह महज 2.8 फीसदी और अप्रैल में 3.96 फीसदी थी।

अक्टूबर और नवंबर को छोड़कर इन सभी महीनों में अन्य अनाजों की महंगाई दर कम होने के कारण गेहूं और चावल की कीमतों ने महंगाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। अक्टूबर में दरों में 1.99 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि सितंबर में 1.37 फीसदी की कमी आई थी। नवंबर में यह थोड़ी नरम होकर 1.7 फीसदी रहीं। गेहूं और चावल की कीमत बढ़ने से गरीबों का बजट बिगड़ सकता है, लेकिन सरकार 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को पहले ही 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर चुकी है।

गरीबों की रसोई संभाल रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त प्रदान किया जाता है। यह उनके मासिक कोटा के अतिरिक्त है। इसके अलावा, राशन वाले चावल और गेहूं की कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली चावल की कीमतों में कैलेंडर वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान अप्रैल तक गिरावट देखी गई। इसके बाद सितंबर तक महंगाई दर 1 फीसदी से नीचे रही। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले चावल की कीमत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पीडीएस गेहूं के मामले में नवंबर 2022 तक कीमतों में हर महीने गिरावट जारी रही।

गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन पिछले साल के स्तर से कम रहा सरकार के अनुमान के मुताबिक, गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन पिछले साल के स्तर से कम रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर घोषित और निजी व्यापारियों की गणना के बीच गिरावट की सीमा अलग.अलग है। यह हाल के इतिहास में बहुत कम देखा गया है, जब दोनों मुख्य अनाजों के उत्पादन में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण गिरावट आई है। 2022 में रबी की कटाई से ठीक पहले गर्मी में अचानक वृद्धि के कारण गेहूं का उत्पादन गिर गया। पूर्वी भारत के मुख्य उत्पादक राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सूखे और कम बारिश के कारण पिछले खरीफसीजन में चावल का उत्पादन गिरा था।

समाप्त होने वाले 2022 के रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन 10.64 करोड़ टन आंका गया था। यह पिछले साल के उत्पादन से 38 लाख टन कम है क्योंकि मुख्य फसल उगाने के चरण में गर्मी की लहर के कारण उत्पादन में कमी आई है। हालांकि, निजी व्यापारियों ने उत्पादन को बहुत कम, लगभग 9.8.10.0 करोड़ टन के आसपास आंका है। उत्पादन में गिरावट के कारण घरेलू बाजार में कीमतों में तेजी आई।

नवंबर में खाद्य तेलों का आयात 34प्रतिशत बढ़कर 15.29 लाख टन पर

कच्चे पामतेल (सीपीओ) और रिफाइंड पाम तेल के आयात में तेज उछाल के कारण भारत का खाद्य तेल आयात नवंबर में 34 प्रतिशत बढ़कर 15.29 लाख टन हो गया। उद्योग संगठन एसईए ने यह जानकारी दी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तेल विपणन वर्ष 2022.23 के पहले महीने नवंबर के लिए खाद्य तेल और गैर.खाद्य तेल सहित कुल वनस्पति तेलों के आयात के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसारए नवंबर 2022 में वनस्पति तेलों का आयात 32 प्रतिशत बढ़कर 15,45, 540 टन हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 11,73,747 टन था।

एसईए ने कहा कि कुल वनस्पति तेल आयात में से खाद्य तेलों का हिस्सा इस साल नवंबर में बढ़कर 15,28,760 टन हो गया, जो 2021 के इसी महीने में 11,38,823 टन था। अखाद्य तेलों का आयात नवंबर में 52 प्रतिशत घटकर 16,780 टन रह गया, जो एक साल पहले की अवधि में 34,924 टन था। एसईए ने कहा कि इसके अलावा खाद्य तेलों की श्रेणी में कच्चे पाम तेल (सीपीओ) का आयात एक महीने में सबसे अधिक रहा। भारत ने नवंबर, 2022 में रिकॉर्ड 9,31,180 टन सीपीओ का आयात किया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 4,77,160 टन रहा था। सीपीओ आयात का पिछला उच्चतम स्तर अक्टूबर, 2015 में 8,78,137 टन का था।

आरबीडी (रिफाइंड) पामोलिन का आयात नवंबर में बढ़कर 2,02,248 टन हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 58,267 टन था। सूरजमुखी तेल का आयात भी 1,25,024 टन से बढ़कर 1,57,709 टन हो गया। हालांकि, कच्चे सोयाबीन तेल का आयात नवंबर, 2021 के 4,74,160 टन से घटकर समीक्षाधीन महीने में 2,29,373 टन रह गया। एसईए ने आरबीडी पामोलिन के अत्यधिक आयात पर चिंता व्यक्त की क्योंकि यह घरेलू रिफाइनरी कंपनियों को प्रभावित कर रहा है। एसोसिएशन ने कहा सीपीओ (पांच प्रतिशत) और रिफाइंड तेल (12.5 प्रतिशत) के बीच 7.5 प्रतिशत का मौजूदा आयात शुल्क अंतर सीपीओ के विपरीत हमारे देश में रिफाइंड पामोलिन के आयात को प्रोत्साहित करता है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तैयार माल का यह आयात राष्ट्रीय हितों के विपरीत है और घरेलू पाम रिफाइनिंग उद्योग की क्षमता उपयोग को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। एसईए ने कहा पामोलिन आयात में वृद्धि का मुख्य कारण निर्यातक देशों (मलेशिया और इंडोनेशिया) द्वारा अपने उद्योग को दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। उन्होंने कच्चे पाम पर उच्च निर्यात शुल्क और पामोलिन तैयार उत्पाद पर कम निर्यात शुल्क रखा है। सीपीओ और रिफाइंड पामोलिन के बीच 7.5 प्रतिशत का आयात शुल्क अंतर आयात को रोकने के लिए अपर्याप्त है।

बीज भण्डार™

क्या आप अपना खुद का व्यापार स्थापित करना चाहते है ?

मध्य भारत की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन आउटलेट बीज भंडार की फ्रेंचाइजी ले और बने अपनी दुकान के मालिक

बीज भंडार की फ्रेंचाइजी लेने के लिए संपर्क करे।
बीज भंडार, जैन एग्रो एजेंसी, खरगोन मोबा. 8305103633

उन्नत खेती के उत्तम बीज

कृषि रसायन आयात नीति का क्या होगा परिणाम ?

खेती करना आसान काम नहीं होता। खेती करने के लिए कई चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है व अनेक परेशानियों से लड़ना पड़ता है। फसल उगाने में सबसे बड़ी चुनौती कीटों एवं बीमारियों से फसल को सुरक्षित करना होता है। फसल कितनी भी स्वस्थ क्यों ना हो, अगर उसमें कीड़े एवं रोगों का प्रकोप हो गया तो फसल नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। फसलों को कीड़ा और बीमारियों से बचाने के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

भारत में तीनों श्रेणियों टेक्निकल, इंटरमीडिएटरी, फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट का कुल आयात 5900 करोड़ रूपए का होता है। कुल आयात में चीन से आयातित कृषि रसायनों की कुल हिस्सेदारी 55 प्रतिशत है। अब इससे ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत- चीन द्वारा उत्पादित कीटनाशक पर कितना निर्भर है।

संपादकीय

प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने हेतु अब कृषि रसायनों के आयात की बहुत कड़ी शर्तें लागू की गई हैं। सरकार अब भारत में इन कृषि रसायनों के टेक्निकल के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहती है। ऐसे में आयात बंद होने से भारत में कीटनाशकों की कमी पड़ेगी क्योंकि बढ़ती मांग के अनुरूप इतनी जल्दी इतनी बड़ी मात्रा में कीटनाशकों के टेक्निकल्स का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इतने बड़े पैमाने पर कीटनाशक निर्माण के लिए उद्यमियों को जल्दी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी? क्या कृषि रसायन उद्योग किसानों के बीच इतनी बड़ी मात्रा में कीटनाशकों की पूर्ति कर सकेगा? क्या उचित समय पर कीट प्रबंधन किया जा सकेगा? क्या किसानों को सस्ते दामों पर कीटनाशक मुहैया करायी जाएगी?

आयात बंद होने से दो मुख्य परिणाम सामने आएंगे। पहला या तो किसानों को कीटनाशकों की अनुपलब्धता होगी या बहुत महंगे हो जाएंगे। सरकार को इस मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि किसान अपनी सारी पूंजी और मेहनत के दम पर अन्न उत्पादन करता है। कहीं ऐसा ना हो कि किसान की फसल सरकार की इस रणनीति में खत्म हो जाए।

कृषि से आय के मामले में पंजाब नहीं मेघालय पहले स्थान पर

हलधर किसान 98262 25025 । प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में पंजाब देश में दूसरे स्थान पर है। राज्यसभा के चल रहे सत्र में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है। मंत्री तोमर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

जानकारी के अनुसार, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय ;29.348 रुपये के साथ मेघालय देश भर में शीर्ष पर है। पंजाब 26,701 रुपये के बाद हरियाणा 22,841 रुपये अरुणाचल प्रदेश 19,225 रुपये, जम्मू और कश्मीर 18,918 रुपये, केंद्र शासित प्रदेशों का समूह 18,511 रुपये, मिजोरम 17,964 रुपये, केरल 17,915 रुपये, पूर्वोत्तर राज्यों का समूह 16,863 रुपये, उत्तराखंड 13,552 रुपये, कर्नाटक 13,441 रुपये, गुजरात 12,631 रुपये, राजस्थान 12,520 रुपये, सिक्किम 12,447 रुपये और हिमाचल प्रदेश 12,153 रुपये है।

बागवानी पर ध्यान दें किसान : अरोड़ा ने मीडिया से कहा, अगर हम मानते हैं कि राज्य नकदी फसलों पर अधिकतम निर्भर हैं, तो पंजाब बागवानी और फलों के प्रमुख हिस्से वाले मेघालय के साथ पहले स्थान पर होगा। उन्होंने पंजाब के किसानों से फसलों, बागवानी और फलों के अधिक विविधीकरण के लिए जाने का आग्रह किया। पंजाब में उत्पादित प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना, तिलहन और कपास शामिल हैं, लेकिन चावल और गेहूं कुल सकल फसली क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा हैं।

गन्ने का मूल्य 360 रुपये से बढ़कर 380 रुपये प्रति क्विंटल हुआ : अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में किसानों की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने ने कहा कि अक्टूबर में मुख्यमंत्री ने गन्ने का मूल्य 360 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 380 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी। यह किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में पंजाब में 1.25 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की जाती है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने का आश्वासन दिया है।

यू- ट्यूब से दूध की वैकल्पिक खेती की सीखी तकनीक, अब तक 6 लाख तक का लिया मुनाफा

हलधर किसान। 98262 25025 खरगोन. सूचना क्रांति के दौर में डिजिटल तकनीक के सहारे संचार माध्यम का सार्थक उपयोग करना भी एक कला ही है। इसी कला की बदौलत शहर से करीब 20 किमी. दूर स्थित रायबिड़पुरा के अनिल वर्मा ने 3 वर्षों में 6 लाख रुपये से अधिक का मुनाफा लिया है। अनिल बताते है कि पहले लॉक डाउन के दौरान महाराष्ट्र के एक किसान से सुरजना के बीज और फलियों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने लगातार यूट्यूब पर इस फसल की जानकारी लेते रहें। इसी समय इसकी खेती की ओर रुचि बड़ी। वर्ष 2019 में मनरेगा से जुड़ने के बाद अब तक सुरजने की खेती से वे 5 बार फसल लेकर 6 वी लेने को तैयार है। इससे उन्हें 6 लाख रुपये तक का मुनाफा हुआ है। सुरजने की आधुनिक खेती के साथ.साथ अंतरवर्ती फसल लेकर बढ़ावा दे रहे हैं।

सफलता की कहानी..

46 वर्षीय बीए की शिक्षा पूरी कर कृषि पेशा अपनाने वाले अनिल हमेशा से कुछ नया करने की फिराक में नवीन तकनीक के सहारे नई.नई तकनीक सिख रहे है। उन्होंने बताया कि सुरजने या मोरिंगा की देश सहित विदेशों में अच्छी मांग है। यह एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ से लेकर शाखाओं तक का उपयोग किया जाता है। इसका पोषण में उपयोग के अलावा आयुर्वेद में बड़ा महत्व माना गया है। इसमें दूध की तुलना में चार गुना अधिक पोटेशियम, 7 गुना अधिक कैल्शियम संतरा की तुलना में 7 गुना अधिक विटामिन पाया जाता है। अनिल इसकी पत्तियों का पॉवडर बनाकर समुचित मात्रा में गेहूं के आटे में मिलाकर भी व्यवसाय भी कर रहे है। इसलिए हड्डी की बीमारियों में तथा बच्चों को कुपोषण दूर करने में उपयोगी है।

300 से अधिक बीमारियों में कारगर

सुरजने का उपयोग न सिर्फभोजन में बल्कि दवा या आयुर्वेद में इसका उपयोग ज्यादा होता है। इसकी फली व सुखी तथा हरी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेड, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरनए मैंगनीशियम और विटामिनों में एए बी और सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन सब के अलावा 18 तरह के अमीनों एसिड मिलता है। इस पौधे की फ्ल, फूल, पत्ती, सब्जी, छाल, पत्ती बीजए गोंद का उपयोग होता है। साथ ही जड़ से आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती है। इसकी जड़, तना, फल, पत्ती, छाल और गोंद से करीब 300 से अधिक बिमारियों में कारगर रूप से उपयोगी हो रही है।

उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी पीएस बड़ोले ने बताया कि रायबिड़पुरा के अनिल के खेत पर मनरेगा के तहत पौध लगाने के लिए डीपीआर बनाई गई थी। इसमें 1200 पौध के लिए 110704 रुपये की मजदूरी की राशि और 21600 रुपये सामग्री के लिए प्रदाय किये गए है। अनिल ने अपनी रुचि से अपने संसाधनों के सहयोग से करीब 2.50 एकड़ में खेती करने लगे है। इसमें ड्रिप सिस्टम उनका ही है। उनकी खेती करने का उत्साह सराहनीय है। वे सुरजने की फ्सल के बीच अंतवर्ती खेती भी करते है। अनिल को मनरेगा से आगे 144000 मजदूरी और 163000 सामग्री की कुल राशि 300000 मिलेगी।

प्रतियां पाने, लेख प्रकाशन के लिए संपर्क करें

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए शोध, अनुसंधान, कृषि सफलताओं, नवाचारों, योजनाओं के प्रकाशन के माध्यम से प्रयासरत है। हलधर किसान, राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र की प्रतियां प्राप्त करने के साथ ही कृषि, पशुपालन, बागवानी, अनुसंधान जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, शोध, खेती में नवाचार जैसे लेख प्रकाशन कराना चाहते है तो हमें वाट्सएप नंबर- 8817402860, 94254 89337 पर भेजे सकते है। हम आपका लेख प्रमुखता से फोटो सहित उचित स्थान पर प्रकाशित करेंगे। अपना नाम, डाक पता और फोन नंबर सहित संपर्क करें।

पाठकों की कलम से...

मेजवानी हो शाकाहारी व्यंजनों से...

भारतीय संस्कृति सदैव से ही शाकाहार की उद्घोषक रही है। नियमित, संतुलित, एवं शाकाहारी भोजन को आयुर्वेद मे स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन का राज बताया गया है। भारत मे मौसम परिवर्तन के साथ ही स्वाद के जायके बदल जाते है साथ ही त्यौहार प्रधान हमारे देश मे विभिन्न राज्यों के विभिन्न समाजो के अपने अपने त्यौहार है और उस त्यौहार के अनुसार व्यंजन भी सेहत के लियें अच्छे माने जाते है, जिसके बेहतरीन स्वाद का भारतीय लुत्फ उठाते है। विडंबना है की वर्तमान मे हमारा शाकाहारी खानपान पश्चिमी खानपान से अतिप्रभावित होता नज़र आरहा है। कुछ दिनों पहले अपने नज़दीक के शहर के एक प्रतिष्ठित मॉल में जाने का मौका मिला, जब मैंने वहां सिर्फ शाकाहारी काउंटर की तलाश की, तब मुझे पता चला की वहां कम से कम एक दर्जन फूड काउंटर में से सिर्फ एक शाकाहारी फूड काउंटर है, जहां शकाहारी भोजन की सुविधा थी बाकी सभी फूड स्टाल में शाकाहारी एवं मांसाहार भोजन एक साथ उपलब्ध था। यें अनुपात मांसाहारी भोजन का पड़ला भरी कर्ता है। सोचने वाली बात है की जिस रसोई में शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन साथ मे पकता हों और एक ही काउंटर से परोसा जाता हों वहां कैसे शाकाहारी व्यक्ति भोजन ग्रहण करेगा? आजकल यह कहकर टाल दिया जाता है की 'सब चलता हैं' यें ही हमारी संस्कृति एवं संस्कारों को आसानी से चलता कर रहे हैं। इतने बड़े मॉल में जहां हरवर्ग हर संप्रदाय की भरी भीड़ आरही हैं वहां मनोरंजन के साथ हमारे शाकाहारी खान पान कोचलता किया जा रहा हैं, और हम उसे मौन स्वीकृति दे रहे हैं...!

बरखा विवेक बड़जात्या
बाकानेर
जिला-धार, मध्य प्रदेश

अधिक संख्या में तो हमारी युवा पीढ़ी ऐसी जगह देखने में आती हैं हम उन्हें क्या संस्कार दे रहे हैं? वो तो ब्रांड नाम स्व. खान स्टेटस सिंबल समझते हैं चाहे वहा फिर कुछ भी मिले, आज मेडिकल में जितना फास्ट फूड से कई नुकसान बताये जा रहे हैं, उतना ही वो युवा पीढ़ी को लुभा रहे हैं। देश की रीढ़ हमारी युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का जिम्मेदार कौन हैं यें चिंतन का विषय है। प्रदेश गौरव हमारा इंदौर शहर कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़े आयोजन की तैयारी में जोर.शोर से लगा है। आजादी के अमृत काल में अप्रवासी सम्मलेन में के मेजवानी शहर ही नहीं देश के लियें गौरव की बात है। हमारे हर आने वाले मेहमानों के लियें हर सुख. सुविधाएं, सुरक्षा एवं मनोरंजन का महत्वपूर्ण ध्यान रखने की तैयारी जोरो पर है।

'पधारो म्हारा घर थीम अथिति देवो भवः' को प्रधानता दे रही है, वही मेरा आयोजको से निवेदन ही कि आयोजन स्थल पर शाकाहार भोजन को महत्व देते हुए हमारे विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यंजनों के स्वाद को हमारे मेहमानों को परोसा जाये जों हमारे मेहमानों को लुभा सके तथा हमारे शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहित कार सके। ऐसे ही विभिन्न प्रांतीय व्यंजन के काउंटर बड़े बड़े मॉल मे भी होने चाहिये ताकि हमारी युवा पीढ़ी भी प्रांतीय शाकाहारी स्वाद से परिचित एवं प्रोत्साहित हों सके एवं अपने ही देश मे विदेशी खान.पान से दूरी बनाया सके एवं मेजवानो के मेजवानी शाकाहारी व्यंजनों से करने मे गर्व महसूस करे।

नसों के गंभीर रोग से बचाने के मामले में रामबाण है हरी पत्तेदार सब्जियां

हलधर किसान। 98262 25025

ईसीयू के स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया जिसमें दावा किया गया कि हरी सब्जियां रक्त वाहिकाओं में होने वाले गंभीर रोगों से हमें बचाती हैं। हरा साग और सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं ये बात हमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में इस विषय और गहन अध्ययन किया गयाणअध्ययनों में पाया गया है कि हमारी कुछ सबसे कम पसंदीदा सब्जियां वास्तव में गंभीर नसों के रोग को रोकने के लिए सर्वोत्तम हो सकती हैं।

कैसे करती है काम ?

ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक अध्ययन के अनुसार, जो वृद्ध महिलाएं ब्रोकोलीए ब्रसेल्स स्प्राउट्स और गोभी सहित हरी सब्जियों का अधिक सेवन करती हैं उनकी ब्लड वेसेल्स कम डैमेज होती हैं।1998 में भर्ती की गई 684 वृद्ध पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के एक समूह के डेटा का उपयोग करते हुए ईसीयू के स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन महिलाओं ने हरी सब्जियों का सेवन अधिक किया था उनकी रक्त वाहिकाओं की दीवार में फैटी कैल्शियम जमा नहीं हुआ था और रक्त का प्रवाह भी सामान्य था। बता दें कि नसों में जमा कैल्शियम ही दिल की बीमारियों का कारण बनते हैं। रक्त वाहिका रोग एक ऐसी स्थिति है जो हमारी नसों को प्रभावित करती है और शरीर के चारों ओर घूमने वाले रक्त के प्रवाह को कम कर सकती है। रक्त के प्रवाह में यह कमी महाधमनी जैसे हमारे रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवारों पर फैटी, कैल्शियम जमा होने के कारण हो सकती है। यह फैटी, कैल्शियम जमा होने से दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा हो सकता है।

दिल का दौरा नहीं पड़ता

प्रमुख शोधकर्ता डॉ लॉरेन ब्लेकेनहोर्स्टने कहा कि क्रसिफेरस सब्जियों के बारे में कुछ दिलचस्प था जिस पर इस अध्ययन ने अधिक प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा, हमारे पिछले अध्ययनों मेंए हमने पहचाना कि इन सब्जियों के अधिक सेवन से हृदय रोग की घटना, जैसे कि दिल का दौरा या स्ट्रोक होने का जोखिम कम था, लेकिन हमें यकीन नहीं था, इस नए अध्ययन से इस बात की पुष्टि हो गई है।

अध्ययन में क्या पाया गया

क्रुसीफेरस सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक विशेष घटक विटामिन के है जो हमारे रक्त वाहिकाओं में होने वाली कैल्सीफिकेशन प्रक्रिया को बाधित करने में शामिल हो सकता है। डॉ ब्लेके नहोर्स्ट ने कहा कि इस अध्ययन में जिन महिलाओं ने हर दिन 45 ग्राम से अधिक क्रुस वाली सब्जियों का सेवन किया (जैसे 1/4 कप उबली हुई ब्रोकोली या 1/2 कप कच्ची गोभी) उनके शरीर में कैल्शियम का व्यापक निर्माण होने की संभावना 46 प्रतिशत कम थी उन लोगों की तुलना में जो हर दिन बहुत कम या कोई क्रूस वाली सब्जियां नहीं खाती हैं। यह जरूरी नहीं कि हमें केवल ब्रोकोली, गोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स ही खाना चाहिए। समग्र अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए हमें हर दिन कई तरह की सब्जियां खानी चाहिए।

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध, तब भी 8 महीने में हुआ 30 प्रतिशत ज्यादा

इस साल देश में गेहूं के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि इस समय आम आदमी के उपयोग का खुला आटा भी 35 रुपए किलो बिक रहा है। बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इस साल मई में ही इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब भी इस साल अप्रैल से नवंबर तक गेहूं के निर्यात में करीब 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी केंद्र सरकार के आंकड़ों से मिली है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद गेहूं का निर्यात पिछले साल से भी ज्यादा रहा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल.नवंबर के दौरान यह 29.29 फीसदी बढ़ कर 1.50 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में 1.17 अरब डॉलर के गेहूं का निर्यात हुआ था। उल्लेखनीय है कि घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकिए अनुरोध करने वाले देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं के थोड़ा बहुत निर्यात करने की अनुमति है।

भारत से इस साल सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात बंगलादेश को हुआ है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास परिषद के आंकड़ों के मुताबिक इस साल बंगलादेश को 4082843 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया गया। इससे भारत को 889,398.88 लाख रुपए मिले। बंगलादेश के बाद भारत से सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात श्रीलंका को किया गया। वहां इस साल अभी तक 582917 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया गया। इसके बाद संयुक्त अरब अमिरात का स्थान रहा।

चावल का निर्यात भी 40प्रतिशत बढ़ा: वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इस साल के शुरुआती आठ महीने में बासमती चावल का निर्यात भी बढ़ा है। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान चावल का निर्यात 39.26 फीसदी बढ़ कर 2.87 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसी अवधि में गैर.बासमती चावल का निर्यात 5 फीसदी बढ़कर 4.2 अरब डॉलर का रहा। चालू वित्त वर्ष के आठ महीनों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 16 प्रतिशत बढ़कर 17.43 अरब डॉलर का हो गया।

इस साल बढ़ा दिया गया है लक्ष्य : मंत्रालय ने कहाए वर्ष 2022-23 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए 23.56 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के आठ महीनों में 17प435 अरब डॉलर का निर्यात पहले ही हासिल किया जा चुका है। इसलिए शेष बचे चार महीने में यह लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाने की संभावना है।

कृषकों के हित में 'न भूतो न भविष्यति' वाला वर्ष रहा है 2022

हलधर किसान। 98262 25025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्म.निर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के हित में राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में अभूतपूर्व निर्णय लिये। ये ऐसे निर्णय रहे, जिनसे किसानों को अप्रत्याशित रूप से दो गुने से ज्यादा लाभ मिला। किसानों का धन और समय बचा, जिसका लाभ उन्हें और उनके परिवार को मिला। हम कह सकते हैं कि किसानों के लिये वर्ष 2022 'न भूतो न भविष्यति' की उक्ति को चरितार्थ करने वाला रहा है।

राज्य सरकार को लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड के अतिरिक्त कृषि अधोसंरचना निधि के सर्वाधिक उपयोग के लिये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, मिलेट मिशन योजना में बेस्ट इमर्जिंग स्टेट और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रदेश में वन ग्राम के किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में शामिल करवा दिया। इससे वनाधिकार पट्टेधारियों की फसलों को क्षति होने पर

श्री कमल पटेल
कृषि मंत्री मप्र शासन

फसल बीमा योजना का लाभ मिलने लगा। फसल बीमा योजना का ज्यादा से ज्यादा किसान लाभ ले सकें और इसमें अपनी विभिन्न फसलों का बीमा कराने के लिये सरकार ने अधिसूचित फसल क्षेत्र का मापदंड 100 हेक्टेयर के स्थान पर 50 हेक्टेयर किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4 हजार रूपये मिला कर प्रदेश के लाखों किसानों को 10 हजार रूपये की सालाना मदद की जा रही है।

प्रदेश में किसानों की ग्रीष्म कालीन मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गयाए जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। चनाए मसूर, सरसों की उपज का उपार्जनए गेहूँ उपार्जन के साथ किया गया। इससे किसानों को लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। सरकार ने 8 जिलों में तिवड़ा मिश्रित चने का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया। प्रदेश सरकार के जितना उत्पादन.उतना उपार्जन के निर्णय से चने के उपार्जन की क्षमता में वृद्धि हुई और किसानों को 750 करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। इस वर्ष समितियों में एक दिन में किसानों से उपार्जन की अधिकतम सीमा 25 क्विंटल को समाप्त कर दिया गया।

किसानों के हित में परंपरागत फसलों के स्थान पर लाभकारी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये फसल विविधीकरण योजना लागू की गई। राज्य में प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिये भी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रत्येक किसान को अपनी कुछ भूमि पर प्राकृतिक खेती के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि नर्मदा नदी के किनारों पर 4 लाख 45 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जायेगी। एक लाख 86 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने के लिये 60 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के प्रोत्साहन के लिये सरकार देसी गाय के लालन.पालन के लिये 900 रूपये प्रतिमाह का अनुदान दिया जायेगा। सरकार ने किसानों के हित में कृषि आदानों की गुणवत्ता नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए अमानक बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रेताओं के विरूद्ध भी इस वर्ष सख्ती से कार्रवाई की। इस वर्ष 136 बीज विक्रेताओं, 120 उर्वरक विक्रेताओं और 14 कीटनाशक विक्रेताओं की अनुज्ञप्तियों को निलंबित और निरस्त करने की कार्यवाही की। बीज, उर्वरक और कीटनाशक के 39 विक्रेताओं के विरूद्ध एफआईआर की कार्रवाई की गई।

राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से प्रदेश में एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय स्वीकृत कराकर चालू कराया गया। यह कार्यालय मंडी बोर्ड भोपाल किसान भवन में स्थित है। इससे मध्यप्रदेश के किसानों को अपने कृषि उत्पाद निर्यात करने में सुविधा मिल रही है। साथ ही उन्हें अपनी उपज का अधिकतम लाभ भी प्राप्त हो रहा है। एपीडा की मदद से ही बालाघाट के चिन्नूर चावल को जीआई टेग मिलने में सफलता मिली है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों को जीआई टेग दिलवाने के लिये एपीडा प्रयासरत है।

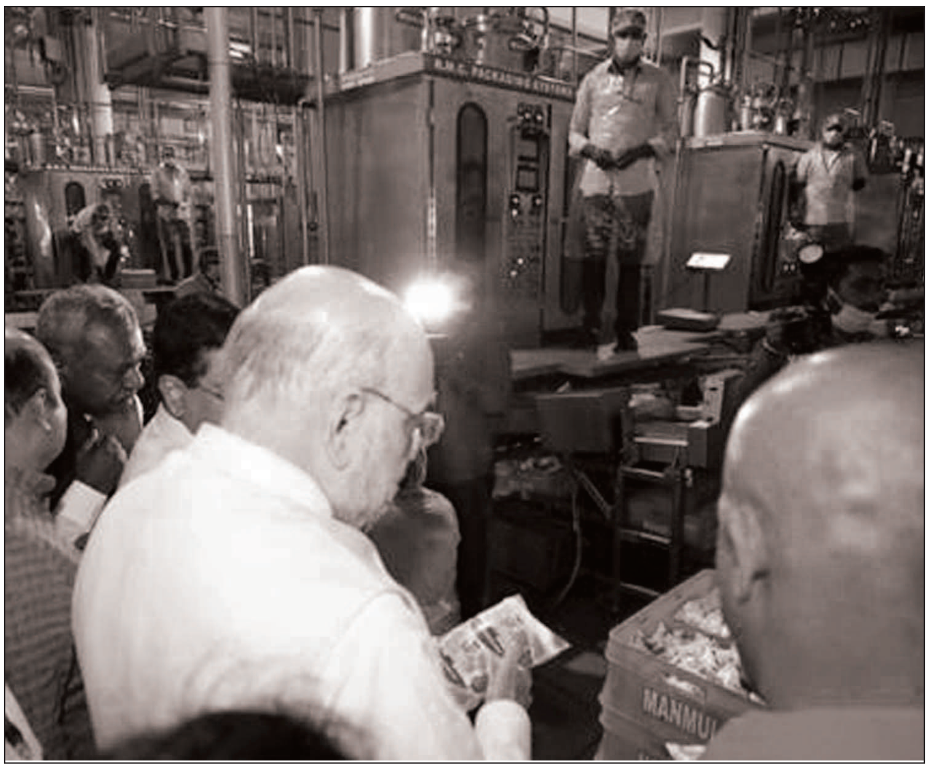

सहकारिता मंत्री शाह ने 260 करोड़ की लागत से बनी मेगा डेयरी का किया उद्घाटन

हलधर किसान। 98262 25025. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या जिले में 260 करोड़ रुपये की लागत से बनी मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आदिचुनचनागिरी महासमस्थान मठ, मांड्या के 72वें स्वामी श्री श्री श्री निर्मलानंदनाथ महास्वामी जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगोड़ा और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी आदि उपस्थित थे।

मंत्री शाह ने कहा कि कर्नाटक में 1975 में प्रतिदिन 66000 किलो दूध प्रोसेसिंग किया जाता था और आज प्रतिदिन 82 लाख किलो मिल्क प्रोसेस किया जा रहा है। खास बात यह है कि कुल टर्नओवर का 80 प्रतिशत किसान के हाथ में जाता है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि गुजरात में श्वेत क्रांति ने किसानों की किस्मत बदल दी है और अमूल के माध्यम से लगभग 36 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में सालाना 60 हज़ार करोड़ रुपये जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे कर्नाटक के सभी किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अमूल और नंदिनी मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे और 3 साल में कर्नाटक में एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां प्राइमरी डेयरी नहीं होगी।

26 लाख किसानों के खाते में हर रोज 28 करोड़ रुपये जाते हैं

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज 260 करोड़ रुपये की लागत से जिस मेगा डेयरी का उद्घाटन हुआ है वह प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध प्रोसेस करेगी और बाद में इसे 14 लाख लीटर प्रतिदिन ले जाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि आज

भारत दुग्ध क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बनेगा

अमित शाह ने कहा कि सरकार ने यह तय किया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय अगले 3 साल में देश की हर पंचायत में प्राइमरी डेयरी की स्थापना करेगा और इसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इससे 3 साल में देशभर में ग्रामीण स्तर पर 2 लाख प्राइमरी डेयरी बनाई जाएंगी, जिनके माध्यम से देश के किसानों को श्वेत क्रांति के साथ जोड़कर भारत दुग्ध क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बनेगा।

कर्नाटक में 15.210 विलेज लेवल कोऑपरेटिव डेयरी हैं, जिनमें प्रतिदिन लगभग 26.22 लाख किसान अपना दूध पहुंचाते हैं और 16 डिस्ट्रिक्ट लेवल डेयरी के माध्यम से 26 लाख किसानों के खाते में हर रोज 28 करोड़ रुपये जाते है। उन्होंने कहा कि केएमएफ का टर्नओवर जो 1975 में 4 करोड़ रुपये था वो अब बढ़कर 25000 करोड़ हो गया है, जिसका 80 प्रतिशत किसानों के खाते में जाता है। उन्होंने कहा कि बोम्बई सरकार डीबीटी के माध्यम से प्रतिवर्ष 1250 करोड़ दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में देने का काम कर रही है।

साथ ही क्षीरभाग्य योजना से बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए 51.000 सरकारी स्कूलों के 65 लाख बच्चों व 64.000 आंगनवाड़ियों में 39 लाख बच्चों को दूध दिया जाता है।

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध, तब भी 8 महीने में 30 प्रतिशत ज्यादा हुआ

हलधर किसान। 98262 25025 इस साल देश में गेहूं के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि इस समय आम आदमी के उपयोग का खुला आटा भी 35 रुपए किलो बिक रहा है। बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इस साल मई में ही इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब भी इस साल अप्रैल से नवंबर तक गेहूं के निर्यात में करीब 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी केंद्र सरकार के आंकड़ों से मिली है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद गेहूं का निर्यात पिछले साल से भी ज्यादा रहा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल.नवंबर के दौरान यह 29.29 फीसदी बढ़ कर 1.50 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में 1.17 अरब डॉलर के गेहूं का निर्यात हुआ था। उल्लेखनीय है कि घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, अनुरोध करने वाले देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं के थोड़ा.बहुत निर्यात करने की अनुमति है।

भारत से इस साल सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात बंगलादेश को हुआ है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास परिषद के आंकड़ों के मुताबिक इस साल बंग्लादेश को 4082843 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया गया। इससे भारत को 889,398.88 लाख रुपए मिले। बंगलादेश के बाद भारत से सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात श्रीलंका को किया गया। वहां इस साल अभी तक 582917 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया गया। इसके बाद संयुक्त अरब अमिरात का स्थान रहा।

चावल का निर्यात भी 40प्रतिशत बढ़ा: वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इस साल के शुरूआती आठ महीने में बासमती चावल का निर्यात भी बढ़ा है। अप्रैल.नवंबर 2022 के दौरान चावल का निर्यात 39.26 फीसदी बढ़ कर 2.87 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसी अवधि में गैर.बासमती चावल का निर्यात 5 फीसदी बढ़कर 4.2 अरब डॉलर का रहा। चालू वित्त वर्ष के आठ महीनों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 16 प्रतिशत बढ़कर 17.43 अरब डॉलर का हो गया।

इस साल बढ़ा दिया गया है लक्ष्य: मंत्रालय ने कहा, वर्ष 2022.23 में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए 23.56 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के आठ महीनों में 17.435 अरब डॉलर का निर्यात पहले ही हासिल किया जा चुका है। इसलिए शेष बचे चार महीने में यह लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाने की संभावना है।

दालों का निर्यात भी बढ़ा है: चालू वित्तवर्ष के आठ महीनों में दाल का निर्यात भी 90.49 फीसदी बढ़ा है। इस साल विभिन्न किस्क के दालों का निर्यात बढ़ कर 39.2 करोड़ डॉलर तक चला गया है। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल.नवंबर के दौरान 33.77 फीसदी बढ़कर 42.1 करोड़ डॉलर रहा जो एक साल पहले इसी अवधि में 31.5 करोड़ डॉलर रहा था।

नारी द्वारा नारी के अधिकारों का हनन...

'नारी के निर्बाध रूप से स्वधर्म पालन कर सकने के लिए बाहरी आपत्तियों से उसकी रक्षा हेतु पुरुष समाज को दिया गया उत्तरदायित्व नारी' है। कथन का तात्पर्य है, कि नारी के मान. सम्मान, धर्म. इच्छाओं का पालन करने का दायित्व समाज ने पुरुष वर्ग को दिया है।

इन उत्तरदायित्वओं का पालन वह बेटा, भाई, पिता, दादा तक के सभी पड़ाव पर स्त्री जाति के प्रति समाज द्वारा तय अपनी मर्यादाओं का पालन करके करना होता है। वही नारी समाज को भी अपनी सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने रिश्ते निभाना, समाज,परिवार को अपने संस्कारों से सींचना भारतीय मातृ शक्ति का प्रथम कर्तव्य मना गया है पर जब 'शील किए संस्कारों कि' मर्यादाओं की दीवारें टूटती है तो असंयमित सीमेंट क्राकरी स्वरूप महिला का अमर्यादित आचरण पूरे समाज के वातावरण को धूमिल कर देती है। परिणाम स्वरूप समाज में नारी शोषण की घटनाएं आम होती नजर आ रही हैं। जैसे की... आपसी सहमति से लिव.इन में रहना सामाजिक व्यवस्था शादी से ज्यादा स्थाई अनुशासित संबंध पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, अति महत्वाकांक्षी स्वभाव के कारण आम होते तलाक के मामले रिश्तो के सम्मान एवं गंभीरता को कम कर रहे है। शादी का झांसा देकर कई सालों तक बलात्कार की शिकार महिला वर्ग की रक्षा के प्रति या तो कानून की उदासीनता या स्वयं महिला वर्ग की अपने अधिकारों के अनुचित उपयोग की मनोवृत्ति को दर्शाता है। यह ही नहीं कई सामाजिक संगठनों को भ्रमित कर उन्हें अपने दायित्व, कर्तव्य, कार्य से भ्रमित करते हैं तथा समाज में विवादास्पद स्थिति को जन्म देते हैं, फलस्वरूप महिलाओं के प्रति समाज मे अविश्वास का माहौल बनता जारहा है। कई प्रकरण सुनने मे आते है जैस..शादी के कई सालों बाद जब खुद के बच्चों की शादी हो चुकी हो या होने वाली हो महिला के प्रति दहेज प्रताड़ना की शिकायत किस सोच को प्रदर्शित करता है।

पाठक की कलम से

नारी की विशिष्टता एवं सदाचार को प्रभावित करने के लिए संविधान में दंड का प्रावधान है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अल्प वस्त्र तरीकाएं नारी चरित्र को प्रदर्शन के पर्दे पर अपमानित करने के रिकार्ड तोड़ रही है और सोशल मीडिया की टीआरपी इसको प्रचारित, प्रसारित करने की होड़ में लगी है। नतीजन नवयुवतिओं में इसका अत्यधिक प्रभाव देखने में आरहा है। लगता है जैसे लौकिक संस्कार धुएं के छल्ले में उड़ रहे है, जीवन के लक्ष्य कि ओर बढ़ने वाले कदम नशे मे लड़खड़ा रहे है! धार्मिक संस्कार 6.7 इंच के मोबाइल कैमरे में सिर्फ दिखावे के लिये कैद हों रहे है। वर्तमान सुशिक्षित विकसित समानता का अधिकार देने वाला भारतीय समाज पाश्चात्य के भोंडे प्रदर्शन की बलि चढ़ता नजर आ रहा है, जो किसी समाज के पतन का कारण हो सकता है। यहां यह चिंतन का विषय है किए नारी शक्ति के संवैधानिक अधिकारों का स्वयं कुछ महिलाओं द्वारा स्वार्थवश उपयोग संविधान एवं कानून के प्रति सम्पूर्ण समाज कि आस्था एवं सम्मान को कम करता है। यहाँ विभिन्न स्तर पर गठित महिला संगठनों को अपनी अहम् भूमिका निभानी चाहिए, महिलाओं द्वारा किये जानेवाले अनैतिक कार्यों का एवं वहीं दूसरी तरफ नारी चरित्र का दूषित प्रदर्शन करने वाली हस्तियों का जमकर विरोध करना हर महिला संगठन का दायित्व होना चाहिए एवं भारतीय महिलाओं के लिये संस्कार शालायें आयोजित कर संस्कारित करना चाहिये, ताकि परिवार एवं समाज कि सृजनकर्ता महिला वर्ग अपने सुसंस्कारों से संस्कारित देश के निर्माण मे अपनी अहम् भूमिका निभा सके। साथ ही चाहें कोई भी जाती वर्ग हों नारी समाज को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का नारी समाज के हित में उचित तरीके से उपयोग हो तथा नारी के द्वारा नारी के अधिकारों का हनन ना हों सके यही संगठन का मुख्य उद्देश होना चाहिए।

लम्पी रोग से डेढ़ लाख और आपदाओं के कारण 26 हजार पशुओं की मौत

हलधर किसान।98262 25025 देश में लंपी वायरस से साल 2022 के दौरान कुल 29 लाख 52 हजार 233 मवेशी प्रभावित हुए और 1 लाख 55 हजार 724 पशुओं की मौत हुई। यह आंकड़े मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में प्रस्तुत किए।

गृह मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के राज्य.वार आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, प्रभावित राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 05.12.2022 तक, कुल 1.784 लोगों की मौत हुई, 26.401 पशुओं की हानि हुई और 18 लाख 89 हजार 582 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ, इस बात की जानकारी आज गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी।

कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी बारिश से फसल का नुकसान

कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारी बारिश से 33 प्रतिशत और उससे फसल हानि से प्रभावित क्षेत्र 10लाख 06 हजार 455 हेक्टेयर है और महाराष्ट्र से हासिल हुई जानकारी के अनुसार, जून से अक्टूबर, 2022 के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के कारण

41.87 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ, इस बात की जानकारी कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।

फसल बीमा

2016.2022 की अवधि के दौरान, देश में किसानों के दावों का कुल लगभग 1लाख 28 हजार 000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 20.000 करोड़ का भुगतान राजस्थान को किया गया है, यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।

अनुबंध खेती

सरकार ने राज्यों को गोद लेने के लिए प्रचलित मॉडल अधिनियमों में अनुबंध खेती का प्रावधान किया है। मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2003 के अनुसार, 15 राज्यों . आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड आदि राज्यों ने अपने राज्य में एपीएमसी अधिनियम अनुबंध खेती का प्रावधान किया है। इस बात की जानकारी कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।

पराली जलाना

कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (सीआईएमएस) प्रयोगशाला द्वारा उत्पन्न उपग्रह आंकड़ों के अनुसार, नई दिल्ली के कृषि भौतिकी विभाग, आईसीएआर . भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, 2021.22 में धान के अवशेषों को जलाने के कारण सक्रिय आग की घटनाएं पंजाब में 71304 मामले, हरियाणा में 6987 मामले और उत्तर प्रदेश में 4242 मामले देखे गए, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को दी।

धान की बुआई के क्षेत्र में कमी

2022.23 (पहला अग्रिम अनुमान) के दौरान खरीफ धान का रकबा 411.16 लाख हेक्टेयर की तुलना में 407.43 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। खरीफ 2021.22 (चौथा अग्रिम अनुमान) के दौरान 3.73 लाख हेक्टेयर (0.91 प्रतिशत) की मामूली गिरावट दर्ज की गई, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

क्या है लंपी स्किन डिसीज

लंपी स्किन डिसीज गायों.भैंसों जैसे मवेशियों में कैप्रिपॉक्स नाम के वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ये बहुत तेजी से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। यह वायरस बकरियों में होने वाले गोट पॉक्स और भेड़ों में होने वाले शीप पॉक्स जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार वायरस जैसा ही है। कैप्रिपॉक्स उसी वायरस फैमिली से आता हैए जिससे स्मॉल पॉक्स और मंकीपॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं। इस रोग के कारण मवेशियों को बुखार और शरीर में गांठें पड़ जाती हैं।

उद्योग की तरह कृषि में भी भारत क्यों नहीं कर पाया चीन की बराबरी?

हलधर किसान। 98262 25025

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने कहा कि भारत में कृषि सुधार 1991 से ही लंबित चल रहे हैं, जबकि पड़ोसी देश चीन ने उन्हें 1978 में ही लागू कर दिया था। 1991 में भारत में किए गए सुधार बाहरी कारकों और औद्योगिक उदारीकरण से संबंधित थे और इनका कृषि से कोई संबंध नहीं था। इस समय कृषि व्यवहार्य नहीं रह गई है और यहां तक कि देश की जीडीपी में इसका हिस्सा भी सालाना एक प्रतिशत घट रहा है। इसके बावजूद देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। देबरॉय ने कहा, भारत में हम अक्सर चीन से तुलना करते हैं। चीन ने 1978.79 में ही कृषि में सुधार कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत में 1991 में सुधार लागू किए गए थे, लेकिन ये सुधार बाहरी क्षेत्र और औद्योगिक उदारीकरण से संबंधित थे। क्या कृषि में सुधार किए गए हैं? क्या कृषि लाइसेंसिंग मुक्त है?इसका जवाब है नहीं, उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र के लागत.उत्पादन, विपणन और वितरण पक्ष को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कृषि के लिए सुधार एजेंडा न केवल 1991 से लंबित है, बल्कि अब भी यह लटका हुआ है प्रौद्योगिकी, बीजए विपणन माध्यम, निवेश और वितरण इनमें से प्रत्येक में आपको नियंत्रण देखने को मिलेगाए ये नियंत्रण दूर नहीं हुए हैं। मूलतः प्रतिरोध की एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। देबरॉय ने कहा कि प्रतिरोध की यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था इस मानसिकता से आती है कि भारतीय किसान अपने लिए अच्छे या बुरे के बारे में नहीं जानते हैं लिहाजा उन्हें संरक्षण देना चाहिए। उन्होंने इस धारणा से असहमति जताते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि किसानों को इस अर्थ में संरक्षित करने की जरूरत है। हां, खेती व्यवहार्य नहीं रह गई है, क्योंकि लागत मूल्य अन्य कीमतों से अधिक हैं। उन्होंने कहा कि बीमा को लेकर कुछ समस्याएं हैं। हमारे पास अभी भी संतोषजनक बीमा नहीं है। लेकिन भारतीय किसानों को संरक्षण की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों को राज्य के अनुचित हस्तक्षेप से बचाने की जरूरत है।

सरकार ने जीएम सरसों पर मंजूरी दिलाने की कोशिशें कि तेज

देश में सरकार स्थानीय तौर पर विकसित जीएम सरसों के लिए जल्द से जल्द मंजूरी लेने की कोशिशें कर रही हैं। अक्टूबर में, देश में देश में विकसित जीएम सरसों के बीजों को पर्यावरण से संबंधित मंजूरी मिली थी। जिससे उसके पहले जीएम कॉर्प के वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए रास्ता खुल गया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उसे यह जानकारी जीएम फसलों का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने दी है।

सरकार का क्या कहना है?

जीएम.फ्री इंडिया के गठजोड़ ने कहा है कि जीएम मस्टर्ड के आकलन और मंजूरी के दौरान जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रैजल कमेटी जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है, उसने बायो सुरक्षा रेगुलेशन्स का उल्लंघन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक,जीईएसी के फैसले पर गंभीर रेगुलेटरी में लापरवाही के आरोप लगे हैं।

सरकार ने इसका जवाब देते हुए एक बयान में कहा कि जीईएसी ने कई सालों के दौरान इक्ट्ठा किए गए संबंधित डेटा के लंबे ट्रायल और कड़ी जांच के बाद जीएस सरसों को मंजूरी दी है। रेगुलेटर ने जीएम सरसों की फसल को मंजूरी देने के लिए हर गाइडलाइन का पालन किया है। ट्रायल के पूरे होने और पर्यावरण जोखिम के आंकलन के बाद देखते हैं।

एनटीपीसी और टेक्निमोंट ने हरित मेथनॉल उत्पादन की संभावना तलाशने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

हलधर किसान। 98262 25025

. भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी. एनटीपीसी ने इटली स्थित मैयर टेक्निमोंट समूह की भारतीय सहायक कंपनी टेक्निमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर.बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में एनटीपीसी की परियोजना में वाणिज्यिक पैमाने पर हरित मेथनॉल उत्पादन की सुविधा विकसित करने की संभावना का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करना और पता लगाना है। इस हरित मेथनॉल परियोजना में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना और इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है। हरित मेथनॉल में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसमें रासायनिक उद्योग के लिए आधार सामग्री के रूप में उपयोग होना, नवीकरणीय विद्युत का भंडारण करना और परिवहन ईंधन के रूप में भी काम आना शामिल है। इसे समुद्री ईंधन अनुप्रयोगों के लिए एक स्थानापन्न ईंधन भी माना जाता है। एनटीपीसी के निदेशक (वाणिज्यिक) सीके मंडल ने कहा कि प्रायोगिक पैमाने पर हरित मेथनॉल परियोजना के तहत एनटीपीसी के साथ यह पहल स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर एनटीपीसी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत में ऊर्जा के रूपांतरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।

क्या है ग्रीन मेथनॉल ?

ग्रीन मेथनॉल में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसमें रासायनिक उद्योगों के लिए आधार सामग्री के रूप में उपयोग, नवीकरणीय विद्युत का भंडारण एवं परिवहन ईंधन के रूप में भी उपयोग करना शामिल है। इसे समुद्री ईंधन अनुप्रयोगों के लिए एक स्थानापन्न ईंधन के रूप में भी माना जाता है। प्रायोगिक पैमाने पर हरित मेथनॉल परियोजना स्थिरता एवं नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर एनटीपीसी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी

एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफइंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह 1975 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4.760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। जेपीएल सौदे से पहले कंपनी की कुल स्थापित व्यावसायिक क्षमता 69454 मेगावाट थी।

गाय के गोबर से बने पेंट से हो रही सरकारी भवनों की पुताई

हलधर किसान 98262 25025। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए राज्य के सरकारी भवनो, स्कूलों और छात्रावासों में गाय के गोबर से बने जैविक पेंट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गाय के गोबर से पेंट बनाने की इकाई राज्य के रायपुर और कांकेर जिले के गौठानों में स्थापित की गई है अगले वर्ष जनवरी के अंत तक सभी जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि गौठानों में इसके निर्माण से स्थानीय महिलाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार ने राज्य में दो वर्ष पहले गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी।

इसके तहत आठ हजार से अधिक गौठान स्थापित किए गए हैं। इन गौठानों में पशुपालकों और किसानों से दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर और चार रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गोमूत्र खरीदा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गौठान समितियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वर्मी.कम्पोस्ट, अगरबत्ती, दीपक, रंगोली पाउडर, दोना.पत्तल आदि कई उत्पादों के निर्माण के लिए सुविधा प्रदान की गयी हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के शुरुआत में राज्य सरकार ने गाय के गोबर से पेंट बनाने के लिए के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था।

वहीं गाय के गोबर से बिजली उत्पादन की तकनीकी सहायता के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ समझौता किया गया था।

23 ईकाईयां करेंगे शुरु

गोधन न्याय योजना के संयुक्त निदेशक आरएल खरे ने बताया कि रायपुर जिले के हीरापुर जरवाय गांव और कांकेर जिले के सरधू नवागांव गांव स्थित गौठानों में प्राकृतिक पेंट का निर्माण शुरू किया गया है। अगले वर्ष जनवरी माह के अंत तक राज्य के सभी जिलों में ऐसी 73 और इकाइयां शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य के बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर जिले के तीन गौठानों में गोबर से बिजली बनाने की इकाई शुरू की गई है। खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के कृषि विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को गौठानों में पेंट निर्माण इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने और सभी सरकारी भवनों की पेंटिंग रासायनिक पेंट की जगह गोबर से बने पेंट का उपयोग करने का निर्देश दिया है।

केंद्रिय मंत्री ने कि सराहना

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राज्य सरकार की पहल की सराहना करते हुए ट्वीट किया था, छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागीय निर्माणों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल का आग्रह करते हुए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन करता हूं। उनका यह निर्णय सराहनीय और स्वागत योग्य है। गडकरी ने लिखा है,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएसएमई मंत्री रहते हमने इसकी शुरुआत की थी। प्राकृतिक पेंट का उपयोग न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि किसानों को रोजगार का एक नया अवसर भी प्रदान करेगा, जिससे देश के किसानों को लाभ होगा।

इको-फ्रेंडली और गंध-मुक्त होता है पेंट

अधिकारी ने बताया कि कार्बोक्सिमिथाइल सेल्युलोज गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का मुख्य घटक है। एक सौ किलो गोबर से करीब 10 किलो सूखा सेल्युलोज तैयार किया जाता है। खरे ने बताया यह पेंट एंटी.बैक्टीरियल, एंटी.फंगल, नॉन.टॉक्सिक, इको.फ्रेंडली और गंध.मुक्त होता है। गाय के गोबर से निर्मित होने वाले पेंट के दो प्रकार की कीमत क्रमशः 120 रुपए प्रति लीटर और 225 रुपए प्रति लीटर है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक लीटर से 130 से 139 रुपए और 55 रुपए से 64 रुपये तक का लाभ प्राप्त होगा। रायपुर के बाहरी इलाके हीरापुर जरवाय गांव में स्थापित इकाई में 22 महिलाओं को जोड़ा गया है और इस वर्ष जून में वहां उत्पादन शुरू किया गया था। रायपुर के पशु चिकित्सालयों सहित सरकारी भवनों की पेंटिंग में गाय के गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल किया गया था, कांकेर जिले के चारामा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीएस बढ़ई ने कहा कि कांकेर में पहली बार स्कूलों और छात्रावासों को इस प्राकृतिक पेंट से रंगा गया है।

कोयला मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको-पार्क किये निर्मित

हलधर किसान। 98262 25025 कोयला मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आठ इको.पार्क निर्मित किए है। खान पर्यटन यानी माइन टूरिज्म में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 तक दो और ऐसे पार्क बनकर तैयार हो जायेंगे।

कोयला मंत्रालय के मुताबिक पुनर्प्राप्त भूमि पर इको.पार्क विकसित करने और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के प्रयासों के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में आठ इको.पार्क बनाए गए हैं। इन पार्कों में लोगों की रुचि को देखते हुए दो और पार्क बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में में डब्ल्यूसीएल के झुरे, बाल गंगाधर तिलक इको.पार्क का उद्घाटन किया था। खान.1और खान.2 में इको.पर्यटन को बढ़ावा देने और सतत खनन गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में पांडिचेरी पर्यटन विकास निगम (पीटीडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।

सिंगरौली इको.पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए एनसीएल और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के बीच एमओयू और डब्ल्यूसीएल द्वारा महाराष्ट्र के पर्यटन निदेशालय के साथ एक अन्य एमओयू भी कोयला क्षेत्र में इको.पर्यटन को बढ़ावा देंगे। वहीं सतत विकास और हरित पहल के अनुरूप कोयला, लिग्नाइट पीएसयू ने इस वर्ष जनवरी से नवंबर तक 2300 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 47 लाख पौधे लगाए हैं।वहीं कोकिंग कोल उत्पादन को और बढ़ाने के लिए, कोयला मंत्रालय ने चार कोकिंग कोल ब्लॉकों की पहचान की है। इसके साथ ही सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ;सीएमपीडीआई आने वाले महीनों में 4 से 6 नए कोकिंग कोल ब्लॉकों के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) को भी अंतिम रूप प्रदान करेगा। घरेलू कच्चे कोकिंग कोयले की आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के लिए बाद के दौर में की जाने वाली नीलामी में इन ब्लॉकों की पेशकश की जा सकती है।

कोयला मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत किए जा रहे इन उपायों से, घरेलू कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन 2030 तक 140 मिलियन टन तक पहुंच जाने की संभावना है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड ने मौजूदा खानों से कच्चे कोकिंग कोल के उत्पादन को 26 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2025 तक लगभग 22 मीट्रिक टन की पीक रेट क्षमता के साथ नौ नई खदानों की पहचान की है। इसके अलावा, सीआईएल ने बंद पड़ी कुल 30 खदानों में से आठ बंद पड़े कोकिंग कोल खदानों की पेशकश की है, जो 2 एमटी पीआरसी के साथ निजी क्षेत्र को राजस्व साझा करने के एक अभिनव मॉडल पर आधारित है।

रीवा, दमोह टीकमगढ़ में सूअरों में फैला अफ्रीकन स्वाइन फिवर

हलधर किसान 98262 25025। मप्र के दमोह जिले के हटा और बनवार में सूअरों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होने के बाद वेटरनरी विभाग ने चार सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनमें हटा से लिए गए सैंपलों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। इसके बाद से सूअर पालकों में हड़कंप मच गया है।। हटा में नवोदय वॉर्ड ककराई के एक किमी के एरिया को संवेदनशील मानते हुए विभाग के निर्देश पर 14 सूअरों को मारकर जमीन में दफनाया गया। पशु चिकित्सा विभाग की टीम हटा में लगातार जांच कर रही है।

विभाग का कहना है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर की कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए हटा में 10 किमी के एरिया में जितने भी सूअर होंगे उन्हें मारना पड़ेगा नहीं तो जिले में संक्रमण और तेजी से फैलेगा। विभाग का कहना है कि सूअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि के बाद दमोह शहरी क्षेत्र को भी सूअर मुक्त करना होगा।

पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने विभागीय अधिकारियों को अफ्रीकन स्वाइन फीवर के विरुद्ध हर तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिले में या आस.पास के जिले में प्रकरण पाते ही भारत और राज्य शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन कर नियंत्रित करने के उपाय करें। श्री पटेल ने कहा कि सूकर में पाई जाने वाली यह घातक बीमारी जूनोटिक होने के कारण मनुष्यों और अन्य पशुओं को प्रभावित नहीं करती है। प्रदेश में रीवा, दमोह और टीकमगढ़ में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। संक्रमित क्षेत्रों में एक किलोमीटर

पशुपालन मंत्री ने दिये सतर्कता के निर्देश

की परिधि में सूकरों की कलिंग और पूर्ण ऐहतियात के साथ दफन करने और 10 किलोमीटर की परिधि की जानकारी मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन की मदद से सूकर के आवागमन, उत्पाद और सूकर बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।

रोग नियंत्रण के लिये राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोग शाला में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसमें सुबह 10 से शाम 6 बजे दूरभाष क्रमांक 0755-2767583 पर संपर्क किया जा सकता है।

पारंपरिक स्वाइन फीवर से भिन्न है अफ्रीकन स्वाइन फीवर

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मिलत.जुलते लक्षणों के कारण पशु पालकों में भ्रम की स्थिति है कि पारंपरिक स्वाइन फीवर भी घातक है। इससे जांच के साथ रोग नियंत्रण भी प्रभावित होता है। पारंपरिक स्वाइन फीवर में टीका उपलब्ध होने के कारण मृत्यु दर कम है और आसानी से नियंत्रित हो जाती है जबकि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का वर्तमान में कोई उपचार नहीं है। बचाव ही रोकथाम एवं नियंत्रण का एकमात्र उपाय है।

जलवायु आपदाओं का साल रहा 2022

भारत, चीन, पाकिस्तान सहित कई देशों को हुआ भारी नुकसान

हलधर किसान।98262 25025- वर्ष 2022 में आई 20 सबसे महंगी जलवायु आपदाओं ने भारत, चीन, पाकिस्तान सहित कई देशों को अरबों डॉलर की चपत लगाई। हालांकि 2022 में आई 10 सबसे महंगी जलवायु आपदाओं की सूची में भारत शामिल नहीं था, लेकिन शीर्ष 20 आपदाओं में मार्च और अप्रैल में भारत.पाकिस्तान में पड़े भीषण गर्मी और लू के कहर को शामिल किया गया है। 2022 की दस सबसे महंगी जलवायु आपदाओं की यह लिस्ट क्रिश्चियन एड द्वारा जारी की गई है। क्रिश्चियन एड की यह रिपोर्ट काउंटिंग द कॉस्ट 2022 ईयर ऑफ्क्लाइमेट ब्रेकडाउन से पता चला है कि 2022 में आई 20 सबसे विनाशकारी जलवायु आपदाओं में तूफान इयान सबसे ऊपर थाए जिसने क्यूबा और अमेरिका को 10.000 करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था। इस तूफान का प्रभाव 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 के बीच दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं पता चला है कि इस तूफान में 130 लोगों की मौत हुई थी जबकि 40.000 से ज्यादा लोगों को मजबूरन अपने घरों को छोड़ना पड़ा था।

70 लाख लोगों को बेघर कर गई थी पाकिस्तान में

आई बाढ़: इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक 14 जून से सितंबर के बीच मानसून में पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ में 1.739 लोगों की मौत हो गई थीए जबकि 70 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ विस्थापित होना पड़ा था। पता चला है कि इस आपदा में पाकिस्तान को 560 करोड़ डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ था। हालांकि विश्व बैंक के मुताबिक इस आपदा में 3.000 करोड़ डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ थाए लेकिन बाकी बीमा न होने के कारण सामने नहीं आया है।

यहां क्रिश्चियन एड ने जलवायु आपदाओं से हुए नुकसान के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वास्तविकता में वो उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश अनुमान केवल उन्हीं नुकसान को दर्शाते हैं जिनका बीमा किया है, जबकि बहुत से देशों में इस तरह की आपदाओं से होने वाले नुकसान का कोई बीमा नहीं किया जाता।

रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और यूके में गर्मियों के दौरान पड़े भीषण सूखे और लू के कहर के चलते 2.000 करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था। वहीं 23 फरवरी से 31 मार्च के बीच पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ में 60.000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। वहीं 750 करोड़ डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ था।

रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील में पड़े सूखे से जहां 400 करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था वहीं चीन में पड़े सूखा में यह आंकड़ा 840 करोड़ डॉलर से ज्यादा दर्ज किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में आर्थिक नुकसान की गणना की गई है। लेकिन आर्कटिक और अंटार्कटिक में 18 मार्च 2022 को आई हीटवेव की घटनाएं भविष्य के लिए बड़े खतरे की ओर इशारा करती हैं। इसी तरह मार्च और अप्रैल के दौरान भारत और पाकिस्तान में लू के कहर ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी।

इसी तरह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में साल भर चले सूखे की वजह से अब तक 3.6 करोड़ लोग सोमालिया, इथियोपिया और केन्या में विस्थापित हुए हैं। वहीं 16 दिसंबर से 19 जनवरी 2022 के बीच मलेशिया में आई बाढ़ में 54 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 70.000 लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा था। इस बारे में संगठन क्रिश्चियन एड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिक वाट का कहना है कि पिछले साल आई 10 अलग.अलग जलवायु आपदाओं में हर किसी आपदा से 300 करोड़ डॉलर से ज्यादा की आर्थिक क्षति हुई है और इसके लिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी निष्क्रियता जिम्मेवार है। उनका कहना है कि डॉलर के आंकड़ों के पीछे मानव नुकसान और पीड़ा की लाखों कहानियां हैं। ऐसे में यदि ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन में कटौती न की गई तो भविष्य में यह मानवीय और वित्तीय त्रासदी केवल और बढ़ेगी। उनके अनुसार जलवायु परिवर्तन की मानवीय कीमत बाढ़ में बह गए घरों, तूफानों से मारे गए प्रियजनों और सूखे से नष्ट हुई जीविका में देखी गई है। उनके अनुसार यदि आप जलवायु संकट की अग्रिम पंक्ति में हैं तो यह वर्ष विनाशकारी था।

जलवायु संकट: ओडिशा, तेलंगाना में समय से पहले बौराए आम

वैज्ञानिकों का तर्क बौरों का जल्दी और अत्यधिक लगना असामान्य

हलधर किसान। 98262 25025

फलों के राजा आम में जलवायु परिवर्तन के बादल छाए हुए है। दिसंबर माह में ही तेलंगाना और ओडिशा में आम के पेड़ में बौरों का आना शुरू हो गया है, जो देखा जाए तो इसके सामान्य समय से कम से कम एक महीने पहले है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए बेमौसम बारिश और सामान्य से ज्यादा गर्म होती सर्दियां जिम्मेवार हो सकती है। देखा जाए तो बेमौसम बारिश और गर्म होती सर्दियां दोनों ही जलवायु में आते बदलावों के निशान हैं।

बैंगलोर स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस में इकोलॉजी के प्रोफेसर एमडी सुभाष चंद्रन ने बताया कि आमतौर पर इस समय दक्षिणी केरल में आम के पेड़ों में फूल आना शुरू हो जाता है। उनके अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि फूलों को गर्मी और नमी की आवश्यकता होती है, जो इस अवधि के दौरान केरल में होती है। यहां से फूलों के खिलने का सिलसिला शुरू होता है जो समय के साथ उत्तर की ओर बढ़ता जाता है, और अंत में उत्तर पश्चिमी भारत में बौर लगने का यह सिलसिला खत्म होता है। उनके अनुसार आम के पेड़ों पर लगने वाली बौर भी इसी दक्षिण से उत्तर के पैटर्न का अनुसरण करती है।

देखा जाए तो तेलंगाना और ओडिशा जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उत्तरी भागों में, यह आमतौर पर शुष्क अवधि होती है। ऐसे में यहां बौरों का लगना जल्दी और अत्यधिक असामान्य है। यदि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी आंकड़ों को देखें तोए 8 से 14 दिसंबरए 2022 के बीच तेलंगाना के 33 में से 16 जिलों में भारी बारिश हुई थी।

आईएमडी ने जानकारी दी है कि संगारेड्डी जिले में जहां डीटीई ने बौरों को देखा है, वहां सामान्य से 735 फीसदी ज्यादा बारिश हुई थी।

गौरतलब है कि यह इस बात को दर्शाता है कि तेलंगाना और ओडिशा में साल की यह अवधि सामान्य से कहीं ज्यादा गर्म है। प्रोफेसर चंद्रन का भी कहना है कि बेमौसम बारिश के अलावा गर्म तापमान भी आम के पेड़ों में बौर लगने को प्रेरित कर सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन से पौधों के विकास के पैटर्न और अप्रत्यक्ष रूप उनकी वानस्पतिक और प्रजनन प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता घट जाती है।

मार्च 2016 में जर्नल इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि जलवायु में आते बदलावों के चलते आम के पेड़ों में समय से पहले और बाद में बौरों का लगना उसकी एक विशेषता है। इसी तरह असामान्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में इस बार फरवरी में ही आम के पेड़ों में बौरों का लगना देखा गया था। बौरों के लगने की यह गति भी काफी तेज थी। वहीं कुछ स्थानों पर कई पेड़ों में बौरों के साथ फल लगने की भी जानकारियां सामने आई हैं। इस बारे में डीटीई में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चला है कि यह आने वाले तूफानी मौसम और तेज गर्मी का संकेत है। गौरतलब है कि विशेषज्ञों के एक वर्ग का मानना है कि मौजूदा शुरुआती फूल भी इसी तरह की स्थिति का संकेत देते हैं।

नर्सरियों के माध्यम से स्व. सहायता समूह की आय बढ़ाने की योजना तैयार

हलधर किसान 9826225025। खरगोन जिले में महिला स्व. सहायता समूहों की आय में वृद्धि करने के लिए योजना तैयार की गई है। ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में कलेक्टर कुमार ने योजना का खांका तैयार कर सम्बंधित विभाग को अमल में लाने के निर्देश दिए है। स्व सहायता समूहों की आय बढ़ाने की दिशा में कलेक्टर ने वॉटर शेड और विशेष रूप से उद्यानिकी विभाग को इसके लिए तकनीकी सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। भगवानपुरा के बलखड़ और खरगोन के लिक्खी गांव में उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में मॉडल स्वरूप उत्कृष्ट स्तर की फ्लों वाली दो नर्सरियां तैयार की जाएगी। इसमें उसी गांव के स्व. सहायता समूह को इस नर्सरी का पूरा ज्ञान प्रशिक्षण देकर कार्य से जोड़ना है। पीओ रमाकांत पाटीदार से कहा कि 15 दिनों में इस संबंध में कार्य स्वीकृत करें। नर्सरी 2 एकड़ या इससे अधिक जगह पर भी हो सकती है। इस नर्सरी का ए ही उद्देश्य है। स्व सहायता समूह की आय हो इस नजरिए से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

वाटर शेड बनाएगा ढाई करोड़ के 13 बड़े तालाब

वॉटर शेड पीओ पाटीदार ने बताया कि 16 दिसम्बर को भगवानपुरा में 9 और खरगोन में 4 नए बड़े तालाब स्वीकृत हुए है। कुल 2.50 करोड़ की लागत से बनने वाले बड़े तालाबो को दोनों जनपदों के सीईओ को कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि आप दोनों की जिम्मेदारी है उत्कृष्ठ स्तर की गुणवत्ता वाले तालाब निर्माण होने चाहिए। ऐसे तालाब बने की मॉडल तालाब हो।

उपयंत्री पर जताई नाराजगी

इस योजना पर पूर्व में 29 सितम्बर को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों पर अमल नहीं करने पर कलेक्टर ने उपयंत्री जावेद खान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ संकेत दिए कि योजना को पूरी करने में कोई कोताही नहीं चलेगी। ग्रामीण यात्रिकी विभाग महेश्वर और खरगोन डिवीजन द्वारा किये गए विभिन्न निर्माण कार्यों के ताजा फोटो देखकर समीक्षा की गई। पूर्व में मियावाकी तकनीक पर किये पौधारोपण के फोटोग्राफऔर अपडेट जानकारी लेने के बाद कलेक्टर ने सभी इंजीनियरों से कहा कि निमाड़ में नीम के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल जलवायु है। ज्यादा से ज्यादा नीम लगाए जा सकते हैं। बैठक में सीएम हेल्पलाईन, एनआरएलएम, पंचायत प्रकोष्ठ, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास, मनरेगा और आयुष्मान कार्ड की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा, अतिरिक्त सीईओ पुरुषोत्तम पाटीदार, समस्त योजनाओं के परियोजना अधिकारी, समस्त जनपदों के सीईओ, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री उपस्थित रहे।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन। Titel Code. MPHIN/2022/37675, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।